

पायलट ने नीरज उधवानी के घर जाकर श्रद्धांजलि दी

जयपुर निवासी उधवानी की पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले में मृत्यु हुई थी



पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी नीरज उधवानी के निवास पर उनको श्रद्धांजलि दी एवं परिजनों को ढाँढस बंधाया।

जयपुर, 27 अप्रैल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी नीरज उधवानी के निवास पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की एवं परिजनों को ढाँढस बंधाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। यह कोई आम आतंकी घटना नहीं है। जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया है वो मंसूबे बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस मसले को आगे कैसे ले जाना है और इसपर क्या कार्रवाई करनी है यह मुद्दा हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमिटी में रखा था। भारत

■ कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि भारत सरकार को पूरी ताकत के साथ आतंकवादी हमले का जवाब देना चाहिये। पूरा विपक्ष और पूरा देश सरकार के साथ हैं।

सरकार को अपनी पूरी ताकत के साथ जवाब देना पड़ेगा। पूरे देश में इसपर एक राय है। उन्होंने कहा, पक्ष विपक्ष हमारे देश के लिए है, आक्रमण बाहर से हो रहा है और हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है, आतंकियों के जरिए तो उनको तो उसी जमान में जवाब देना चाहिए। जब पहले इस प्रकार भारत की संसद पर आक्रमण किया गया था उस समय

आम भावना है कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से जो धाव देश को दिए हैं उसका समापन करना पड़ेगा। पायलट ने कहा, इस दुःख की घड़ी में पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। जिल लोगों ने कोशिश की है कि देश में दरार पड़े, मजहब के नाम पर, और यही उनके मंसूबे हैं, हमें उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। इस संकल्प के लिए पूरा देश, सभी राजनैतिक पार्टी, हर व्यक्ति एकजुट है। जिन्होंने अपने खोए हैं वो वापिस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन, इतना हम कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई साहस नहीं करें।

पाकिस्तान ने तीसरी रात भी सीमा पर गोलीबारी की

भारतीय सेना ने गोलीबारी का प्रभावी जवाब दिया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है

एनआईए ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सेना की हालत खराब है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर नीलम वैली राजमार्ग पर सामान्य दिनों के मुकाबले ट्रकों की गतिविधि कई गुना बढ़ी हुई है। भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए ज्यादातर गतिविधियाँ सिविल ट्रकों में हो रही है।

भारतीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भारतीय नौसेना ने एक्स पर लिखा, "भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आरएसएस सूरत ने समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जो हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में एक और मील का पथर है।"

प.बंगाल में गोरखाओं की केन्द्र शासित प्रदेश की माँग ने जोर पकड़ा

गोरखा पार्टियों का कहना है कि 2019 से भाजपा को पूरा समर्थन दिया, पर उनकी माँगों पर गौर नहीं किया गया

दार्जिलिंग, 27 अप्रैल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में गोरखाओं के बीच एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और उन्होंने अब केंद्र शासित प्रदेश (यूनियन टैरिटरी/यू.टी.) के गठन की माँग पर जोर देने का फैसला किया है।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम), गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (जीएनएमफ), गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा (जीएमएम) और क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (आरसीएमपी) जैसे दलों ने अलग राज्य और गोरखाओं के हितों के मुद्दे पर नया आंदोलन छेड़ने के संकेत दिए हैं।

इन दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2009 से लेकर अब तक पहाड़ में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया है, परंतु आज तक गोरखाओं की मूल मांगों को उचित सम्मान नहीं दिया गया। इन दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने गोरखाओं को केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया, परंतु जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए

■ गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष दवा पाखरीन ने कहा कि गोरखा समाज अपने अधिकारों के लिये निर्णायक आंदोलन करेगा।

कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष दवा पाखरीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि गोरखा समाज एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए निर्णायक आंदोलन करें। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यदि वास्तव में गोरखाओं के हितों की रक्षा करनी है, तो पहाड़ को 'केंद्र शासित प्रदेश' का दर्जा दिया जाए।

इसके साथ ही कुछ दल पहाड़ को अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में शामिल करने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष स्वायत्तता देने की भी मांग कर रहे हैं। परंतु इस पर भी व्यापक

सहमति नहीं बन पाई है, और क्षेत्र में 1954 के एक्जाम एक्ट के समाप्त हो जाने के बाद कानूनी स्थिति भी बदल चुकी है।

दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और आसपास के गोरखा बहुल इलाकों के लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि जब तक इस क्षेत्र को विशेष संवैधानिक दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक गोरखाओं के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली, करता है। इस ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जबकि राहुल गांधी ट्रस्टी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल पहली बार 30 अप्रैल को अमेटी आ रहे हैं। इससे पहले वे 17 मई 2024 को चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे।

देश की एकता दिखाने के लिये संसद का विशेष सत्र बुलायें

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को राजनीतिक दलों से विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाने का सरकार से आग्रह करें। सिब्बल ने कहा, 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि इस दुख की घड़ी में देश की एकता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द ऐसा सत्र बुलाने का आग्रह करें।

इससे पहले कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया था, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि देश एकजुट है। सिब्बल ने सरकार को विभिन्न महत्वपूर्ण देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी सुझाव दिया था, ताकि पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जा सके।

हाई कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर डेढ़ लाख रू. का हर्जाना लगाया

बिजली विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता ने जनहित याचिका में उत्पादन निगम व एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम को रद्द करने की माँग की थी

जयपुर, 27 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया। जनहित याचिका में मु. अभियंता ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को रद्द करने की मांग की थी।

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजय चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने इस याचिका को स्वार्थ प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर यह संयुक्त उद्यम भविष्य में बिजली की महंगी दरों की ओर ले

■ अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल अपनी कल्पना के आधार पर यह दावा किया है कि इस तरह की व्यवस्था से उत्पादन लागत बढ़ सकती है।

जाएगा, जो जनहित के खिलाफ है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने देखा कि यह संयुक्त उद्यम छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के आसपास कई परियोजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से किया गया, जिससे अतिरिक्त उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जा सकें और उत्पादन लागत घटे। अदालत ने कहा कि मामले में सिर्फ इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता बिजली विभाग

में अभियंता रहे हैं। याचिकाकर्ता ने केवल अपनी कल्पना के आधार पर यह दावा किया है कि इस तरह की व्यवस्था से उत्पादन लागत बढ़ सकती है। दर निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनकी जांच इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका कुछ कर्मचारी संघों के हित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित लगती है, जो इस संयुक्त उद्यम का विरोध कर रहे हैं, जैसा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध अभ्यावेदनों से स्पष्ट है। न्यायालय ने कहा कि यह जनहित याचिका न्यायालय के समय और संसाधनों की बर्बादी है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए इसे अस्वीकार के साथ खारिज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 1.50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

मोटर साइकिल को बचाने में वैन कुएं में गिरी, 10 की मौत

वैन व मोटर साइकिल टकराकर खेत में बने बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरीं

- वैन में सवार 10 लोग नीमच जिले में माता मंदिर दर्शन के लिये जा रहे थे, जब यह हादसा हुआ।
- वैन में बैठे लोगों में से 8, मोटर साइकिल चालक तथा रेस्क्यू करने के लिये कुएं में उतरे एक व्यक्ति की मौत हो गई।

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुएं में गए एक व्यक्ति सहित कुल दस लोगों की मौत हो गयी।

दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। घटना के बाद जिला एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मृतकों में दो लोग मंदसौर के निवासी हैं, जबकि वैन सवार सभी मृतक रतलाम के रहने वाले बताए गए हैं।

दुर्घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया

आखिर सेंथिलबालाजी व पोनमुडी को मंत्री पद से हटाया

चेन्नई, 27 अप्रैल। अदालतों की नाराजगी के बाद, जैसा कि व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी, तमिलनाडु के वरिष्ठ मंत्री वी सेंथिलबालाजी और के पोनमुडी को रविवार रात राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया।

राजभवन की ओर से जारी एक विज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सिफारिशों पर राज्यपाल आर एन रवि ने इसे स्वीकार कर लिया।

सेंथिलबालाजी, जिन्हें पिछले वर्ष सितम्बर में विद्युत, निषेध और आबकारी विभागों के साथ मंत्रिमंडल में पुनः शामिल किया गया था, को "नौकरों के लिए नकदी" घोटाले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार करने के बाद मंत्री पद या जमानत पर नियंत्र लेने के लिए सोमवार (कल) तक का अल्टीमेटम दिया गया था।

वहीं, पोनमुडी, हिंदू धर्म से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ हाल ही में अपमानजनक और असभ्य टिप्पणी करने के लिए एमट्रास उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वतंत्रता कार्यवाही का सामना कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप विपक्षी दलों ने उनकी कड़ी निंदा की।

भारत की ओर से झेलम नदी से पानी छोड़े जाने से पीओके में बाढ़ की चेतावनी

यह पानी पाकिस्तानी अधिकारियों को सूचित किये बिना अचानक छोड़ा गया

■ दुनिया न्यूज के अनुसार शनिवार को भारत की ओर से झेलम नदी से अचानक पानी छोड़े जाने से अफरतफरी मच गई और पाकिस्तानी अधिकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हट्टियन बाला जिले में जल आपातकाल की घोषणा कर दी।

■ पाकिस्तान ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे 'अंतरराष्ट्रीय नियमों और जल समझौतों का पूर्ण उल्लंघन' बताया और कहा कि वह भारतीय आक्रामकता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा।

जल समझौतों का पूर्ण उल्लंघन' बताया और कहा कि वह भारतीय आक्रामकता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत की ओर से हालांकि इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है, लेकिन इस कदम से पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है।

गौरतलब है कि गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि आतंकवादी हमले के जवाब में, भारत ने सिंधु जल संधि को तुरंत रोक लगाने की घोषणा की थी। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने उच्चायोग में सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को अवॉर्छित घोषित कर उन्हें निष्काहित कर दिया, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया, सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने को कहा, तथा पाकिस्तान में अपने राजनयिक मिशन को कम कर दिया।

पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को न्याय मिलेगा: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' की 121 वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया

■ उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले से देश का हर व्यक्ति पीड़ा और आक्रोश में है।

महसूस कर रहा है। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कारगरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल-कॉलेजों में चहल- पहल थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ तेरती हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश और जम्मू-

कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। उन्होंने, "आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं, कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया।

मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता, आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वही आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया-भर से संवेदनाएं आ रही हैं।